

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1216  
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय

†1216. श्री अरु वंद गणपत सावंतः  
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः  
श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

- (क) क्या सरकार को जानकारी है क देश में अनेक विद्यालय संबंधित राज्य सरकारों से मान्यताप्राप्त किए बिना संचालित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों से मान्यता/अनुमति के बिना विद्यालयों की स्थापना और संचालन के संबंध में कोई नियम/दिशानिर्देश/मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने वगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे विद्यालयों के प्रबंधन के वरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संवधान की समवर्ती सूची का एक विषय है। केन्द्र सरकार के स्वामित्व/वत्तपोषित वाले विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालय संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इस लिए ऐसे स्कूलों के प्रबंधन से संबंधित मामले जो केन्द्र सरकार के स्वामित्व/वत्तपोषित नहीं है। संबंधित राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों के अनुसार वनियमत किए जाते है। इस प्रकार, गैर-मान्यताप्राप्त स्कूलों के प्रबंधन के वरुद्ध उन्हें नियमत करना/कार्रवाई करना संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार का विषय है।

तथापि, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम, 2009) के अंतर्गत, छह से चौदह वर्ष के आयु तक के प्रत्येक बच्चे को निकटवर्ती

वद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटों की सीमा तक आरक्षण तथा ऐसे बच्चों को शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अधदेश करती है।

साथ ही, आरटीई अधिनियम की धारा 19 में निर्धारित है कि इस अधिनियम के लागू होने के पहले स्थापित और इन मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले ऐसे वद्यालय इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष पहले इन मानदंडों को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे। इस अधिनियम में यह भी अधदेश है कि यदि ऐसे वद्यालय इन मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो मान्यता वापस ले ली जाएगी और वद्यालय कार्यशील नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने यूडाइज कोड के साथ कार्यशील गैर-मान्यताप्राप्त ऐसे वद्यालयों की सूचना निर्धारित की है और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ गैर-मान्यता प्राप्त वद्यालयों के ब्यौरा साझा किए हैं ताकि उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके। गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या के राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

गैर-मान्यता प्राप्त वद्यालय के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अर वंद गणपत सावंत, श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री अनिल यशवंत देसाई द्वारा पूछे गए दिनांक 08.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1216 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्यसंघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या का ब्यौरा (2024-25)

राज्यसंघ राज्य क्षेत्र	गैर-मान्यताप्राप्त वद्यालयों की संख्या (2024-25)
आंध्र प्रदेश	108
अरुणाचल प्रदेश	28
असम	2475
बिहार	4159
छत्तीसगढ़	12
हरियाणा	641
जम्मू और कश्मीर	12
झारखंड	5701
कर्नाटक	1
केरल	765
मध्य प्रदेश	12
महाराष्ट्र	182
मणिपुर	83
मेघालय	491
मजोरम	57
ओडिशा	945
राजस्थान	26
तमिलनाडु	165
तेलंगाना	44
त्रिपुरा	45
उत्तराखंड	11
पश्चिम बंगाल	3555
भारत	19518

स्रोत: यूडाइज+

\*\*\*\*\*